

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी:- श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 09/2017

अनवान :-

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

-: बनाम :-

1. श्री दीनदयाल पुत्र श्री मोहनलाल व्यास मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी शनि मन्दिर के पास पूगल फांटा गजनेर रोड़, बीकानेर -प्रो. (मालिक)
2. श्री रामानन्द व्यास पुत्र दीनदयाल व्यास मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी शनि मन्दिर के पास पूगल फांटा गजनेर रोड़, बीकानेर- (विक्रेता)
3. श्रीमती सीमा देवी सोल प्रो. मैसर्स अग्रवाल एण्ड संस कोयला गली अलख सागर रोड़, बीकानेर
4. श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री एम.पी. जैन मैनेजर एवं नोमिनी मैसर्स मॉडर्न डेयरीज लि. 136 किलोमीटर स्टोन जी.टी.रोड़ करनाल(हरियाणा)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से - श्री महमूद अली खा.सु.अ.
2. अप्रार्थीगणों की तरफ से - श्री सुरेन्द्र आसीजा एडवोकेट

: निर्णय :

दिनांक 30.10.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.08.2016 को अप्रार्थीपक्ष श्री दीनदयाल पुत्र श्री मोहनलाल व्यास मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी शनि मन्दिर के पास पूगल फांटा गजनेर रोड़, बीकानेर -प्रो. (मालिक) के यहां निरीक्षण के दौरान दुकान पर गते के डिब्बे में पैकड घी(श्वेता) 500 ml x 8 नग बेचा जा रहा था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैकेटों में से 500 ml x 4 पैकेट घी(श्वेता) वास्ते जांच नमूना हेतु क्रय किये जिसकी कुल कीमत रूपये 1000/- विक्रेता को नगद देकर माल खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान व प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त क्रय किये गये घी(श्वेता) के 4 पैकेट पर लेबल फॉर्म तैयार कर उनपर विक्रेता, गवाहान स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक पैकेट पर लेबल फार्म चिपका कर, प्रत्येक पैकेट को एक मोटे मजबूत खाकी कागज में लपेटकर अच्छी तरह गोंद से चिपका कर एवं उन पर पेपर स्लिप कोड नम्बर एवं सीरियल नम्बर जे- 1265 को प्रत्येक पैकड नमूना पर राउण्ड दी बोटल प्रक्रिया से प्रत्येक पैकेट को मजबूत व मोटे डोरे से बांध कर प्रत्येक पैकेट को चार-चार जगह



||  
अति. जिला कलक्टर  
(प्रशासन). बीकानेर

दोनों साईडो पर सील चपड़ी कर उन पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने किये तथा मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, पढ़ाकर, समझाकर उनके हस्ताक्षर कराये व स्वयं खा.सु.अ. ने किये। उक्त सीलड पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 10.10.2016 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें घी(श्वेता) सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगणों द्वारा घी(श्वेता) सबस्टेण्डर्ड स्तर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों की तरफ से श्री सुरेन्द्र कुमार आसीजा एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से घी(श्वेता) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./2685/एक्ट/2016/3126 दिनांक 10.10.2016 के अनुसार इस मामले में अप्रार्थी के यहां घी(श्वेता) Reichert Value Shall be Min. 28.0 की तुलना में 27.61 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी(श्वेता) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार कर अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि आवेदक द्वारा उत्पाद का नमूना लिये जाने के संबंध में प्रतिपक्षी संख्या 4 को फॉर्म प्रेषित नहीं की गयी जबकि उक्त प्रकार की सूचना प्रेषित किये जाने एवं मानक अधिनियम 2006

स्वीकृति without application of mind के जारी की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2.1.10(2) में घी के मानक का प्रावधान किया गया है। जिसमें राजस्थान राज्य में घी का मानक Reichert Value (a) Areas other than Jodhpur district-26(b) Jodhpur district-21 दर्शाया गया है और सैम्पल जांच रिपोर्ट विश्लेषक ने घी(श्वेता) की जांच में Reichert value- 27.61 दर्शायी है। अधिनियम एवं उससे संबंधित विनियमों में जिसमें कम से कम Reichert Value 26 होनी चाहिए का प्रावधान होने के बावजूद भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिपक्षी के उत्पाद को अविधिक रूप से एवं अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत सबस्टैण्डर्ड बताया है जबकि प्रतिपक्षी का उत्पाद पूर्ण रूप से सही एवं मानक स्तर का है। प्रतिपक्षी का सैम्पल उच्च एवं मानक स्तर का होने के बावजूद अवमानक स्तर का बताकर आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक ने बिना Agmark seal के उत्पाद के उत्पादक के राज्य के प्रावधान को बीकानेर में लागू नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता ने अन्त में यह भी कथन किया कि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां स्वीकार फरमायी जाकर आवेदक का आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे एवं प्रतिपक्षीगण को शास्ति के दायित्व से मुक्त किया जाने का आदेश फरमावें।

5. इसके विपरीत प्रार्थी पक्ष की ओर प्रस्तुत जवाब में विभागीय प्रतिनिधि ने अप्रार्थी पक्ष की बहस का खण्डन करते हुवे कथन किया कि दिनांक 30.08.2016 को प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थी की दुकान पर निरीक्षण दौरान घी (श्वेता) के पैकड पैकेट बेचा जा रहा था। इस घी (श्वेता) का नमूना लेने हेतु अप्रार्थी पक्ष एवं गवाहान के सामने प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना की गई तथा नमूना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को नियमानुसार वास्ते जांच हेतु भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी को पुनः जांच करवाने सूचित किया गया था। परन्तु अप्रार्थी ने पुनः जांच हेतु आवेदन नहीं किया। परिवादी आवेदक द्वारा मौके पर प्रतिपक्षी 1 को ही फॉर्म वीए के जरिये उक्त उत्पाद का नमूना वास्ते प्रयोगशाला जांच हेतु लेने की जानकारी प्रदान की गई। शेष प्रतिपक्षीगण 2, 3 वारन्टी के अभाव में फॉर्म नं. वीए प्रेषित करना संभव नहीं था, निर्माता, वितरक सप्लायर को न्याय निर्णयन आवेदन में प्रतिपक्षी संख्या 1 की ओर से उपलब्ध सूचनाए वारन्टी के आधार पर क्रमवार अनुसंधान करने पर प्रतिपक्षी बनाया गया है, मौके पर कार्यवाही के दौरान प्रतिपक्षीगण 2, 3 एवं 4 के नाम पते और भी सूचना बिना वारन्टी के फॉर्म नं. वीए प्रेषित करना संभव नहीं था। खाद्य विश्लेषक द्वारा उक्त उत्पाद के नमूने की जांच FSSA के प्रावधानों के अनुसार ही की है तथा खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट नियमों में प्रावधानों के अनुसार ही भिजवाई गई है। घी(श्वेता) को निर्मित करने वाली कम्पनी हरियाणा प्रान्त की है और हरियाणा में ही Minimum Reichert value-



प्रति. जिला कलक्टर  
(प्रशासन), बीकानेर

Areas other than Cotton tract areas में 28 है। उक्त उत्पाद हरियाणा में निर्मित है। केवल Cotton tract areas में ही Reichert value 26 है। जो जांच रिपोर्ट में घी(श्वेता) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। अतः अप्रार्थीपक्ष के द्वारा FSSA की धारा 26(2) का जुर्म कारित किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टिया प्रमाणित होना पाया जाता है इसलिए अप्रार्थीपक्ष को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 30.08.2016 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी पक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण पैकिंग घी(श्वेता) 500 ml x 8 नग मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। जहां तक अप्रार्थी पक्ष का यह कथन की निरीक्षण के द्वारा नमूने लिये जाने के समय प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की एवं FSSA की पूर्ण पालना नहीं की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है। वरवक्त निरीक्षण नमूने लिये जाते समय FSSA एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना निरीक्षण प्रार्थी द्वारा की गई है। नमूने अप्रार्थी एवं गवाह की उपस्थिति में लिये गये है। लिये गये नमूने में से प्रथम नमूना नियमानुसार जांच हेतु भेजा गया है जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.10.2016 के अनुसार जांच परिणाम के अनुसार सबस्टेण्डर्ड फूड पाया गया है। यह जांच रिपोर्ट आने के पश्चात FSSA प्रावधानों के अन्तर्गत ही स्टेट द्वारा अप्रार्थीपक्ष को अवगत करवाया गया है। इस पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन नहीं किया। प्रश्नगत उत्पाद का विक्रय राजस्थान में किया गया है जबकि इसका उत्पादन/विनिर्माण हरियाणा में हुआ है जहां पर मानक 28 है। जांच रिपोर्ट विश्लेषक ने नमूना घी(श्वेता) की जांच में घी की Reichert value- 27.61 पायी। हरियाणा में ही Minimum Reichert value- Areas other than Cotton tract areas में 28 ही है। उक्त उत्पाद हरियाणा में निर्मित है। केवल Cotton tract areas में ही Reichert value 26 है। जांच रिपोर्ट में घी(श्वेता) को सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। पत्रावली में मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक एल.एस/2685/एक्ट/2016/3126 दिनांक 10.10.2016 के अनुसार इस मामले में अप्रार्थी के यहां घी(श्वेता) Reichert Value Shall be Min. 28.0 की तुलना में 27.61 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी(श्वेता) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। जो की एफएसएसए की धारा 26(2) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।



॥  
 अति. जिजा कलक्टर  
 (प्रशासन). बी.काणे

7. लिहाजा अप्रार्थी द्वारा घी (श्वेता) सबस्टेण्डर्ड विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (II) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है। लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा घी (श्वेता) सबस्टेण्डर्ड विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (II) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।
8. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ घी (श्वेता) सबस्टेण्डर्ड का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 1,00,000/- अखरे रूपये एक लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।
9. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।
10. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही खाद्य पदार्थ घी (श्वेता) सबस्टेण्डर्ड का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 4 का ही परिलक्षित होता है। अतः आरोपित कुल शास्ति राशि में से रूपये 50,000/- अखरे पचास हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 4 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात् अप्रार्थी संख्या 4 व भरने हेतु दायी होंगे।
11. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 (विक्रेता एवं मालिक) एवं अप्रार्थी संख्या 3 वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री घी (श्वेता) का विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (II) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 4 विनिर्माता की शास्ति राशि को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति राशि रूपये 50,000/- अखरे पचास हजार रूपये में से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की शास्ति राशि रू. 20,000/- यानि 10,000/-, 10,000/- रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 भरने हेतु दायी होगा तथा अप्रार्थी संख्या 3 वितरक की



॥  
अति. जिला कलेक्टर  
(प्रशासन). बीकानेर

शास्ति राशि रूपये 30,000/- भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,00,000/- (अखरे एक लाख रू) में से 50,000/- रूपये (अखरे पचास हजार रूपये) अप्रार्थी संख्या 4 (विनिर्माता), अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 विक्रेता प्रत्येक 10-10 हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 3 वितरक रू. 30,000/- शास्ति अदा करेगें।

12. इसके साथ-साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 ता 4 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

( ए.एच.गोरी )

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

